RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 02 MARCH 2022 TO 08 MARCH 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 26 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिका देगा 3 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल Page 2

जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने वाले ये हैं 5 राज्य, ई-वे बिल का नया रिकॉर्ड Page 3

यूक्रेन संकट की वजह से एलआईसी के आईपीओ को टाल सकती है सरकार Page 4

editoria!

मेडिकल शिक्षा हो सुलभ

यूक्रेन संकट के कारण वहां पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है. उन्हें सुरक्षित भारत लाने की कोशिशें जोरों पर हैं, लेकिन अगर यह लड़ाई अधिक दिनों तक जारी रहती है या अस्थिरता कायम रहती है, इन छात्रों की पढ़ाई अधूरी रह सकती है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सलाह बेहद अहम है कि छोटे देशों में मेडिकल शिक्षा हासिल करने के बजाय हमारे छात्र देश में ही दाखिला लें. उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि ऐसे देशों में भाषा को लेकर भी मुश्किलें होती हैं. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का नाम नहीं लिया, पर मौजूदा संदर्भों में उनके कहने का आशय समझा जा सकता है. देश में मेडिकल कॉलेजों की कम संख्या और निजी संस्थानों की भारी फीस के कारण छात्रों को यूक्रेन जैसे देशों का रुख करना पड़ता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है. हाल ही में सरकार ने यह निर्देश भी जारी किया है कि निजी मेडिकल कॉलेज 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी शिक्षण संस्थाओं से अधिक नहीं रख सकते हैं. इन उपायों से यह उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और बहुत से छात्र कम शुल्क देकर डॉक्टर बन सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों का आह्वान किया है कि वे ऐसी नीतियां बनायें, जिनसे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन आवंटन में आसानी हो सके. हमारे देश में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी कमी है. इस वजह से हमारी स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. ज्यादातर डॉक्टर और अस्पताल शहरी क्षेत्रों में हैं. इससे न केवल ग्रामीण आबादी और दूर-दराज के इलाकों में रहनेवाले लोगों को असुविधा होती है, बल्कि उन्हें अधिक खर्च भी करना पड़ता है. उल्लेखनीय है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े सुधारों के साथ-साथ केंद्र सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को लगभग दोगुना बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पादन का 2.5 फीसदी तक करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. इससे स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के अलावा डॉक्टरों, नर्सों आदि की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. राज्य सरकारें भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, पर इसकी गति बढ़ाने की जरूरत है. भारतीय छात्रों के विदेश जाने से भारी मात्रा में धन भी बाहर चला जाता है. अनेक देशों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्नचिह्न लगते रहते हैं. ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशों में ही बस जाते हैं. यदि मेडिकल समेत हर तरह की पढ़ाई की व्यवस्था देश में ही सुलभ होगी, तो प्रतिभा पलायन को भी रोका जा सकता है. साथ ही, भू-राजनीतिक संकटों से भी अपने होनहारों को बचाया जा सकेगा. आशा है, केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में अपनी कोशिशों को तेज करेंगी.

क्रूड 110 डॉलर के पार, महंगे पेट्रोल डीजल के लिए रहें तैयार

25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल टैक्स में कटौती करके सरकार दे सकती है राहत

एजेंसी

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से कच्चा तेल भड़क उठा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) के भाव बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं। इस बीच अंतरराष्?ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने की चेतावनी दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा। जिससे क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं।

ग्लोबल एग्रीमेंट के अनुसार कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जापान, अमेरिका सहित ईं के सदस्यों ने अपने रिजर्व में से 6 करोड़ बैरल तेल जारी करने की तैयारी की है, लेकिन यह एक दिन के तेल खपत से भी कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत और बढ़ सकती है। ईं ने कहा है कि अमेरिका ने अपने ऑइल रिजर्व में से 3 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी किया है। हालांकि, जिस तरह दुनियाभर में तेल की खतप बढ़ रही, रिजर्व में रखे तेल इसके लिए काफी नहीं होंगे। कोरोना से पहले दुनियाभर में रोजाना 10 करोड़ बैरल तेल की खपत हो रही थी।

150 डॉलर तक जा सकता है कच्चा तेल

ग्लोबल फर्म गोल्डमैन सैश, मॉर्गन स्टैनली और व्हमॉर्गन ने कच्चे की कीमतों पर भविष्यवाणी की है। इन एजेंसियों के अनुसार कच्चे तेल के दाम जल्द ही 150 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर सकते हैं। हालांकि, रूस ने अपने क्रूड के दाम रिकॉर्ड स्तर तक घटा दिए हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप की ओर से लगे प्रतिबंधों की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा।

119 दिनों से स्थिर हैं दाम

रुझान बताते हैं कि पिछले 119 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जबकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़त हुई है और यह दो महीने के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल पार कर गई हैं। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल 33 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम

एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधान सभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं इसके बाद पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं। क्योंकि आमतौर देखा गया है कि तेल कंपनियां चुनाव के दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाती हैं। महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली लहर में दो बार में पेट्रोल-डीजल पर लगले वाली एक्साइज ड्यूटी में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसके बाद 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी। इक्रा की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है और इसे कोरोना पूर्व स्तर पर लेकर आती है तो सरकारी खजाने पर करीब 92 हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा। 10 मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद कीमत में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ऐसे में कीमत पर कंट्रोल लाने के लिए सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी में कटौती का विकल्प है। ऐसा नहीं करने पर महंगाई बेकाबू हो जाएगी।

भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल करता है आयात

हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल-डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल, यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।

कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिका देगा 3 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल

एजेंसी।

रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले और उसके बाद रूस पर लगाये गए आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है. कच्चे तल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के पार जा पहुंची है। वहीं रूस पर लगाये गए प्रतिबंधों के चलते माना जा रहा है कि दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिकी रणनीतिक आरक्षित भंडार रिजर्व से करोड़ों बैरल तेल देने का फैसला किया है।

बाइडन के मुताबिक उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का व्यपाक असर हो. उन्होंने संकल्प लिया कि उनका प्रशासन अमेरिकी कारोबार और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। बाइडन ने कहा, मैं सभी अमेरिकियों के प्रति ईमानदार रहूंगा जैसा कि मैंने हमेशा वादा किया है। रूसी तानाशाह ने दूसरे देश पर हमला किया है और इसका भार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अमेरिका ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर दुनिया भर के तेल रिजर्व (आरक्षित भंडार) से छह करोड़ बैरल तेल देने का फैसला किया है। अमेरिका इस पहल का नेतृत्व करेगा और हम अपने रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित भंडार से तीन करोड़ बैरल तेल जारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो आगे और कच्चा तेल उपलब्ध कराया जाएगा।

रूस है कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक

रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को थामा नहीं गया तो कच्चे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं जिससे भारत समेत उन देशों की मुसीबत बढ़ेगी जो आयातित कच्चे तेल पर निर्भर हैं। दरअसल रूस दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। रूस यूरोप को उसके कुल खपत का 35 फीसदी कच्चा तेल सप्लाई करता है। भारत भी रूस से कच्चा तेल खरीदता है। दुनिया में 10 बैरल तेल जो सप्लाई की जाती है उसमें एक डॉलर रूस से आता है. ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने से कीमतों में और अधिक तेजी आ सकती है।

विमान ईंधन की कीमत 3.3 प्रतिशत बढ़ी, इस साल पांचवीं बार वृद्धि

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें सात साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ ही देश में विमान ईंधन की कीमतों में मंगलवार को 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते इस साल विमान ईंधन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ऊइ) की कीमतों में यह पांचवीं बढ़ोतरी है।

दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 116वें दिन स्थिर बनी रहीं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमत 3,010.87 रुपये प्रति किलोलीटर या 3.22 प्रतिशत बढ़कर 93,530.66 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन की लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सामानों की आवाजाही होगी महंगी, स्वेज नहर ने लिया यह फैसला

काहिरा। एजेंसी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल परिवहन अब और महंगा हो गया है। नकदी संकट का सामना कर रहे स्वेज केनाल अथॉरिटी ने टोल बढ़ा दिया है। यह टोल स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर लगता है। इसमें दस फीसदी तक की वृद्धि की गई है। यह फैसला एक मार्च 2022 से लागू हो गया है।

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक

स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। तभी तो अधिकतर देशों के कार्गो

लदे जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के टोल में बढ़ोतरी का मतलब है कंटेनर परिवहन के शुल्क में भी बढ़ोतरी। स्वेज केनाल अथॉरिटी (SCA) ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर शुल्क में वृद्धि की घोषणा की। अथॉरिटी ने नहर सेवा के विकास और बेहतरी का हवाला देते हुए कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि के अनुरूप है।

किसमें कितनी बढ़ोतरी

बयान के अनुसार तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, रासायनिक टैंकरों और अन्य तरल थोक टैंकरों के पारगमन शुल्क में दस फीसदी की वृद्धि की जाएगी। वही वाहनों, प्राकृतिक गैस, सामान्य कार्गो और बहुउद्देश्यीय जहाजों को ले जाने वाले जहाजों के लिए पारगमन शुल्क में सात फीसदी की वृद्धि की गई है। इसके अलावा तेल और अन्य टैंकरों और ड्राई कार्गो जहाजों के पारगमन पर लगने वाले शुल्क में पांच फीसदी की वृद्धि की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्वेज नहर के अधिकारी जलमार्ग के दक्षिणी हिस्से को चौड़ा और गहरा करने के लिए मार्च 2021 से काम कर रहे हैं।

रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध से भारत को भी हो रहा नुकसान

निर्यातकों के 500 मिलियन डॉलर फंसे

एजेंसी

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। उस पर आर्थिक लगाम भी लगाए गए हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का असर भारत के निर्यातकों पर भी पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत के निर्यातकों का रूस में लगभग 400-500 मिलियन डॉलर का भुगतान लंबित है और वे पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा में लगे हुए हैं। इस बीच 10 हजार डालर से ज्यादा विदेशी मुद्रा के साथ रूस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है।

कहा जा रहा है कि भारत के फार्मा और कृषि क्षेत्र को स्विफ्ट प्रतिबंधों से बाहर रखने के साथ ही, इनमें से भारत के निर्यातक अपनी बकाया राशि के भुगतान को प्राप्त करने के बारे में आशावादी हैं, लेकिन अन्य सेक्टर के निर्यातक अभी तक प्रतिबंधों के आसपास एक रास्ता नहीं निकाल पाए हैं। उनके लिए अपने पैसे को पाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके लिए सरकार ने परामर्श के लिए निर्यातकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रूस में चल रहे हालात और वर्तमान शासन में वहां हो रहे कुछ बदलावों को और व्यवसायों को लेकर रूसी खरीदारों से अपना बकाया प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की कोशिश में है।

जिस तरह से शीव के रूप में शिपिंग लाइनों के साथ रूस से डिलीवरी को निलंबित कर दिया गया है, इससे ताजा खेप भेजने के लिए निर्यातकों को समस्या हो रही है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद शिपिंग लाइनों ने आदेश स्वीकार करना बंद कर दिया था। लेकिन निर्यातकों की वर्तमान चिंता उन शिपमेंट के बारे में अधिक है जो पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिसके लिए कुछ विकल्पों पर चर्चा की जा रही है।

रूस में आयातक अपनी मुद्रा रूबल में लेनदेन कर सकते हैं, हालांकि इसे प्राप्त करने में समस्याएं आ रही है?। इसके अलावा, निर्यातकों को मानदंडों में छूट की जरूरत नहीं होगी और उन्हें निर्यात लाभ उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, जिससे भेजी गई खेप बेकार हो जाएगी और उसके पैसे मिलेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं. पहले किए गए भुगतान के लिए भारत में निर्यातकों ने कुछ छूट की मांग की है।

'इंडियन प्लास्ट टाइम्स' के स्वामित्व एवं अन्य विवरण के संबंध में

घोषणा पत्र

फार्म-4 (नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशक का स्थान	:	इंदौर
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	सचिन बंसल
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	:	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	-
पता	:	18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	:	सचिन बंसल
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	:	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	-
पता	:	18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)
5. प्रधान संपादक का नाम	:	सचिन बंसल
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	:	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	-
पता	:	18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों :	:	नहीं

मैं **सचिन बंसल** एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 02 मार्च 2022

हस्ताक्षर
सचिन बंसल
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

कीमतें बढ़ने से दैनिक उपयोग के सामान की खपत पर पड़ा असर: नीलसन

नयी दिल्ली। एजेंसी

रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पाद बनाने वाली भारतीय कंपनियों (एफएमसीजी) को वर्ष 2021 में मुद्रास्फीति की वजह से शहरी बाजारों में खपत में सुस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ा। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली फर्म नीलसन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ऊंची मुद्रास्फीति से परेशान इन कंपनियों को बार-बार कीमतों में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालत यह हो गई कि वर्ष 2021 में एफएमसीजी उद्योग को लगातार तीन तिमाहियों में अपने मार्जिन को बचाने के लिए दहाई अंक में दाम बढ़ाने पड़े। इसकी

वजह से वर्ष 2020 की तुलना में बीते साल कीमत-नियंत्रित वृद्धि 17.5 फीसदी पर पहुंच गई। नीलसन आईक्यू की खुदरा बुद्धिमत्ता टीम की बनाई गई एफएमसीजी स्नैपशॉट रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही में भी एफएमसीजी उद्योग को मुद्रास्फीति दबावों की वजह से खपत में 2.6 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा। इसके मुताबिक, वर्ष 2021 के दौरान बढ़ी हुई मुद्रास्फीति ने लगातार तीन तिमाहियों में दहाई अंकों में कीमतें बढ़ाने के लिए कंपनियों को मजबूर किया था। इससे शहरी बाजारों में खपत में सुस्ती आई जबकि ग्रामीण बाजारों में खपत गिर गई। एफएमसीजी कंपनियों की कुल बिक्री में करीब 35 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण बाजारों का है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद इस पर तगड़ी मार पड़ी और एचयूएल समेत कई एफएमसीजी कंपनियों के तिमाही नतीजों में ग्रामीण बिक्री में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। नीलसन की रिपोर्ट कहती है कि कीमतें बढ़ने से छोटे उत्पादकों पर असर पड़ रहा है। इस वजह से 100 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले छोटे विनिर्माताओं की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी हो चुकी है।

नेपाल को उर्वरक की आपूर्ति करेगा भारत, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

काठमांडू। एजेंसी

भारत ने नेपाल के किसानों को रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे नेपाल को उर्वरक की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमओयू पर भारत की ओर से रसायन एवं उर्वरक सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी और नेपाल के कृषि सचिव डॉ गोविंद प्रसाद शर्मा ने एक वर्चुअल समारोह में हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत भारत द्वारा नेपाल को यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी। इस समारोह में नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्री महिंद्रा रे यादव और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने वाले ये हैं 5 राज्य, ई-वे बिल का नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली।एजेंसी

आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और कर चोरी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की बदौलत जीएसटी राजस्व संग्रह में लगातार बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। इस वर्ष फरवरी में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.33 लाख करोड़ रुपये के पार रहा।

जीएसटी लागू होने के बाद यह पांचवां ऐसा महीना है जिसमें जीएसटी राजस्व संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। फरवरी में दैनिक आधार पर ई-वे बिल का भी नया रिकॉर्ड बना है। जीएसटीआईएन के डाटा के अनुसार, फरवरी के पहले 27 दिनों में रोजाना 24.47 लाख ई-वे बिल बने हैं। सितंबर 2018 में ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने के बाद यह संख्या सबसे ज्यादा है। एक से 27 फरवरी के दौरान कुल 6.6 करोड़ ई-वे बिल बने हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी होता है। यह जीएसटी संग्रह का सूचक भी होता है। हालांकि, मासिक आधार पर पिछले साल अक्टूबर में सबसे ज्यादा 7.35 करोड़ ई-वे बिल बने थे। वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 133026 करोड़ रुपये रहा है, जो फरवरी 2021 में संग्रहित 1,13,413 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 2020 में सहंग्रित राजस्व की तुलना में 26 फीसदी अधिक है। इस वर्ष जनवरी में यह राशि 1,40,986 करोड़ रुपये रही थी। इस वर्ष फरवरी में कुल संग्रहित जीएसटी राजस्व में सीजीएसटी 24,435 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,779 करोड़ रुपये , आईजीएसटी 67,471 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर 10340 करोड़ रुपये रहा है। आईजीएसटी में आयात पर जीएसटी 33,837 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर में आयात पर जीएसटी 638 करोड़ रुपये शामिल है।

शीर्ष-5 राज्यों का जीएसटी संग्रह

महाराष्ट्र	19,423 करोड	21%
कर्नाटक	9,176 करोड	21%
गुजरात	8,873 करोड	08 %
तमिलनाडु	7,393 करोड	05 %
उत्तर प्रदेश	6,519 करोड	09 %

गत्ते के बक्से बनाने वालों का केंद्र से जीएसटी दर में कमी का आग्रह

चेन्नई। एजेंसी

गत्ते के बक्से बनाने वाले विनिर्माताओं के एक संगठन ने केंद्र से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लाभ के लिये इन बक्सों पर लगने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने का आग्रह किया है। 'साऊथ इंडियन कोरुगेटेड बॉक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन' ने मंगलवार को कहा कि यदि गत्ते के बक्से बनाने वाले विनिर्माता कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि के कारण होने वाले नुकसान की वजह से इस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो एमएसएमई क्षेत्र को कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। एसोसिएशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि गत्ते के बक्से पर माल एवं सेवा कर 18 प्रतिशत है। यह वित्तीय तनाव का कारण बनता है क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र को भुगतान प्राप्ति में 60 दिन तक का समय लगता है, लेकिन सरकार को शुल्क के रूप में भुगतान 30 दिनों में करना होता है।

यूक्रेन और रूस के युद्ध से रू. 7000 प्रति 10 ग्राम तक हो सकता है सोने का दाम

इंदौर। सर्राफा व्यवसाई संतोष वाधवानी रत्न विशेषज्ञ द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में गोल्ड की नई कीमत रू. 52500 पहुंच चुकी है वहीं चांदी का भाव 68000 प्रति किलो तक पहुंच गया है संतोष वाधवानी द्वारा संभावना व्यक्त की युद्ध के चलते सोने चांदी जैसी कीमती धातु की कीमतें बढ़ेगी और आगामी भविष्य में गोल्ड रू. 70000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना है वहीं चांदी रू. 100000 प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना है उल्लेखनीय है कि सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं का व्यापार बुलियन मार्केट के जरिए होता है।

एटीएल ने भारत के ऊर्जा संक्रमण में अपने योगदान के लिए मान्यता प्राप्त की

एमएनआरई ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एटीएल को बधाई दी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी, अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल), को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय ऊर्जा संवाद के संदर्भ में अपनी एनर्जी कॉम्पैक्ट प्रस्तुत करने और भारत के ऊर्जा संक्रमण में योगदान करने के लिए मान्यता दी गई है। । नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवनमें केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम, आजादी का अमृत महोत्सव, में एटीएल को सम्मानित किया गया। ऊर्जा संक्रमण में भारत के नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए एमएनआरई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी शामिल थे।

अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड के एमडी एवं सीईओश्री अनिल सरदाना ने कहा कि'टिकाऊ (सस्टेनेबल) और नवाचार वाले समाधानों के जरिये, एटीएल बिजली के उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और एसडीजी7लक्ष्योंके अनुरूप सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने के लिए काम करते हुए जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने में योगदान देता है। पारेषण प्रदाता और ऊर्जा वितरक के रूप में हमारी भूमिका भी टिकाऊ शहरों और समुदायों को लेकर एसडीजी11लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और बिजली तक लगातार और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करते हैं।'

एटीएल ने स्वैच्छिक ऊर्जा समझौता (वालंटरी एनर्जी कॉम्पैक्ट) प्रस्तुत करके और पर्यावरण से संबंधित सभी पहलुओं में हितकारी और पर्यावरण-अनुकूल बनकर एसडीजी7लक्ष्यों को हासिल करके ऊर्जा संक्रमण में अग्रणी होने के भारत के संकल्प को दोहराया है। एसडीजी7 2030 तक हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के एक समूह को परिभाषित करता है। इन लक्ष्यों में सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना और वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में काफी हद तक बढ़ाना शामिल है। एटीएल अपनी सहायक कंपनी, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के माध्यम से वित्त वर्ष 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के अपने हिस्से को 3ज से बढ़ाकर 30ज और वित्त वर्ष 2030 तक 70ज करने के लिए तैयार है। इसे प्राप्त करने के लिए, एईएमएलने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 70ज नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एटीएल ने अपनी व्यावसायिक रणनीति को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एसडीजी7 और जलवायु कार्रवाई के लिए एसडीजी 13 की उपलब्धि के आसपास केंद्रित किया है।

यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूसी ए-400 की डिलीवरी पर क्या असर पड़ेगा?

नई दिल्ली।एजेंसी

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद पहली बार भारत में रूसी राजदूत डेनिस ओलिपोव ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध, भारत से संबंध और ए-400 आदि को लेकर अपनी बात रखी है। ओलिपोव ने खारकीव में भारतीय छात्र नवीन की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। हम भारतीय छात्र की मौत की जांच करेंगे।

उन्होंने बताया है कि हम खार्कीव सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों से संपर्क में हैं। हम एक सुरक्षित गलियारा बनाने पर काम कर रहे हैं।

ए-400 पर क्या बोला रूस?

यूक्रेन युद्ध शुरू करने को लेकर रूस पर दुनिया के देशों द्वारा तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम ए-400 में देरी की आशंका को लेकर उन्होंने कहा कि भारत को ए-400 की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हमने प्रतिबंधों से निपटने के लिए तंत्र बनाया हुआ है। वैसे भी प्रतिबंध इस तरह के सौदे में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

यूक्रेन युद्ध और भारत को लेकर?

ओलिपोव ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के लिए रूस को दोष देना आसान है लेकिन यूक्रेन में आठ साल पहले ही युद्ध शुरू हो गया था। रूस और भारत रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में भारत को यूक्रेन मसले से जुड़े लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूनाइटेड नेशंस में भारत के संतुलित रवैए के लिए बेहद आभारी है। भारत हालात की जटिलता को बेहतर तरीके से समझता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा।

छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए नकदी डालने की आवश्यकताः परिधान निर्यातक

कोयंबटूर। एजेंसी

चालू वित्त वर्ष में तिरुपुर में तैयार वस्त्रों का निर्यात 32,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाने की संभावना है। लेकिन निर्यातकों ने रूस के यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर प्रतिकूल प्रभाव होने की आशंका व्यक्त की है। तिरुपुर निर्यातक संघ (टीईए) ने कहा कि पिछले दस महीने में निर्यात 26,030 करोड़ रुपये रहा। सोमवार को चेन्नई में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन में टीईए ने कहा कि पिछले 15 महीनों में कच्चे माल, सूती धागे की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ-साथ सहायक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने नकदी के मोर्चे पर एमएसएमई को प्रभावित किया है। टीईए के अध्यक्ष राजा एम षणमुगम ने कहा कि निर्यात ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त करने के बाद भी लागत की भारी वृद्धि ने उनकी नकदी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इकाइयाँ महीने भर पहले 300 रुपये में एक किलो सूती धागा खरीद रही थीं, वे अब इतनी ही राशि में केवल आधा किलो की खरीद कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि नतीजतन, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) अब नकदी संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि परिधान निर्यात क्षेत्र की 95 प्रतिशत इकाइयां एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं और उन्हें पटरी पर लाने के लिये ताजा नकदी डाले जाने की आवश्यकता है। टीईए ने मंत्री से एमएसएमई को अपनी लागत निकालने में मदद करने, निर्यात आदेश प्राप्त करने और विकास के रास्ते पर बढ़ने में मदद करने के लिए एक और दो साल के लिए निर्यात कर्ज सुविधा योजना (इंटरेस्ट एक्वलाइजेशन स्कीम) के विस्तार की घोषणा करने का अनुरोध किया।

यूक्रेन संकट की वजह से एलआईसी के आईपीओ को टाल सकती है सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

रूस-यूक्रेन संकट गहराने से वैश्विक वित्तीय बाजारों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मेगा आईपीओ को कुछ समय के लिए स्थगित कर अपनी हिस्सेदारी का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने बुधवार को कहा, ''रूस-यूक्रेन विवाद अब पूरी तरह युद्ध का रूप ले चुका है लिहाजा हमें एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्थिति का आकलन करना होगा।''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उभरती भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलआईसी के आईपीओ की समीक्षा किए जाने के संकेत दिए थे। उन्होने कहा था, ''आदर्श रूप में, मैं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि हमने विशुद्ध रूप से भारतीय सोच के आधार पर इसकी योजना बनाई थी। लेकिन अगर वैश्विक परिस्थितियां इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर रही हैं तो मुझे इस पर नए सिरे से गौर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।'' देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा एलआईसी का निर्गम इसी महीने बाजार में आने की उम्मीद जताई जा रही थी। एलआईसी ने 13 फरवरी को पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष आईपीओ का मसौदा पत्र पेश किया था। सरकार चालू वित्त वर्ष में 78,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस जीवन बीमा कंपनी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 63,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही थी। यदि एलआईसी के आईपीओ को अगले वित्त वर्ष के लिए टाल दिया जाता है तो सरकार संशोधित विनिवेश लक्ष्य को बड़े अंतर से पूरा नहीं कर पाएगी। इस वित्त वर्ष में अब तक सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री के जरिए 12,030 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। सरकार ने पहले वर्ष 2021-22 के दौरान विनिवेश से 1.75 लाख रुपये जुटाने का अनुमान लगाया था लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी या 632.49 करोड़ से अधिक शेयर हैं। शेयरों का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एक बार सूचीबद्ध होने के बाद, एलआईसी का बाजार मूल्यांकन रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस जैसी शीर्ष कंपनियों के आसपास होगा। सरकार ने एलआईसी के विनिवेश की सुविधा के लिए इस सार्वजनिक कंपनी में स्वचालित मार्ग से 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी थी। इस संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया था। दरअसल मौजूदा एफडीआई नीति में एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस मेगा आईपीओ में विदेशी निवेशकों के शामिल होने की इच्छा को देखते हुए एफडीआई प्रावधान में बदलाव किया गया है।

भारतीयों को लाने के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा, C-17 ग्लोबमास्टर ने रोमानिया के लिए भरी उड़ान

नई दिल्ली। एजेंसी

यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने 'ऑपरेशन गंगा' तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल हैं। इतना ही नहीं भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्रॉफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा। एयरफोर्स का C-17 एयरक्रॉफ्ट यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए रवाना हो गया है। C-17 ग्लोबमास्टर ने हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। दूसरी

तरफ, रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीयों से बातचीत की है।

भारतीय यूक्रेन से निकले

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन में करीब 20000 भारतीय फंसे थे। तब से करीब 12000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यह यूक्रेन में फंसे कुल भारतीयों का 60% है। उन्होंने कहा, बचे हुए 40% में आधे खारकीव में फंसे हैं. बाकी आधे संघर्ष क्षेत्र से बाहर हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हमारे सभी नागरिकों ने कीव छोड़ दिया है, हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक कीव में हमारे और नागरिक नहीं हैं, वहां से हमें किसी ने संपर्क नहीं किया है।

8 मार्च तक 46 फ्लाइट भेजेगी सरकार

यूक्रेन के खारकीव में रूसी हमले में छात्र नवीन की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया है। ऑपरेशन के तहत भारत 28 फरवरी से 8 मार्च तक बुडापेस्ट, बुखारेस्ट समेत अन्य स्थानों पर कुल 46 फ्लाइट भेजेगा। बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट्स जाएंगी। इनमें 13 एयरइंडिया की, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइसजेट की और एक इंडियन एयरफोर्स का एयरक्रॉफ्ट होगा। वहीं, बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट्स जाएंगी. इनमें से 7 इंडिगो की, 2 एयरइंडिया की और एक स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी। जबकि Rzeszow पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट, Kosice में स्पाइस जेट की एक फ्लाइट जाएगी। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है। जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 180, इंडिगो की 216 और स्पाइस जेट की 180 यात्रियों की क्षमता है।

एयरपोर्ट पर रेल टिकट बुकिंग की मिलेगी सुविधा

भारतीय रेलवे ने भी यूक्रेन से लाए जा रहे छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन से लाए जा रहे छात्र अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रेल टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर ही बुकिंग काउंटर शुरू कर दिया गया है। आईआरसीटीसी के टिकट बुकिंग केंद्र से यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्र आराम से अपने गंतव्य तक जाने के लिए टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे।

जब भारत का तिरंगा लेकर यूक्रेन से निकले पाकिस्तान और तुर्की के स्टूडेंट्स

बुखारेस्ट (रोमानिया)। एजेंसी

यूक्रेन में रूस की बमबारी से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत के तिरंगे झंडे ने न सिर्फ वहां फंसे भारतीय नागरिकों की जान बचाई बल्कि पाकिस्तान (और तुर्की के नागरिक भी युद्धग्रस्त देश से बचकर निकलने में कामयाब रहे। यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुंचे भारतीय छात्रों ने जो बताया, वह हर भारतीय को गौरवान्वित कर सकता है। भारतीयों ने बताया कि तिरंगे ने न केवल उन्हें कई चेक पॉइंट्स को सुरक्षित तरीके से पार करने में मदद की बल्कि कुछ पाकिस्तानी और तुर्किश छात्र भी आसानी से निकल लिए।यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। ऐसे में यूक्रेन से रोमानिया के शहर पहुंचे ये भारतीय छात्र विशेष विमानों से लाए जा रहे हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ानें लगातार यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत पहुंच रही हैं।

बाजार से स्प्रे पेंट और परदा खरीदा

दक्षिणी यूक्रेन के ध्ें से आए

एक मेडिकल स्टूडेंट ने बताया, 'यूक्रेन में हमें बताया गया था कि भारतीय होने और भारतीय झंडा लिए होने के कारण हमें कोई समस्या नहीं होगी।' स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे उन्होंने भारतीय झंडा तैयार करने के लिए बाजार से स्प्रे पेंट खरीदा। एक स्टूडेंट ने बताया, 'मैं बाजार की तरफ भागा, कुछ कलर स्प्रे खरीदा और एक परदा भी ले लिया। मैंने परदे के कई हिस्से कर लिए और फिर स्प्रे पेंट की मदद से भारत का तिरंगा झंडा तैयार किया।'

पाकिस्तानियों ने थामा तिरंगा

उन्होंने बताया कि कुछ पाकिस्तानी और तुर्किश स्टूडेंट्स भी भारतीय झंडा लेकर चेकपॉइंट्स पार कर गए। एक भारतीय स्टूडेंट ने कहा कि ऐसे वक्त में भारत के तिरंगे झंडे ने पाकिस्तानी और तुर्किश छात्रों की बहुत मदद की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी भारत का तिरंगा अपने हाथों में लिए हुए थे। ध्ें से आए ये छात्र मोल्डोवा से रोमानिया पहुंचे। एक स्टूडेंट ने बताया, 'हमने ओडेसा से एक बस बुक की और मोल्डोवा बॉर्डर तक पहुंचे। मोल्डोवा के नागरिक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें फ्री में रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई और टैक्सी व बसों का इंतजाम किया जिससे हम रोमानिया पहुंच सकें।' भारतीय स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें मोल्डोवा में ज्यादा समस्या नहीं हुई क्योंकि भारतीय दूतावास ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। स्टूडेंट्स ने यूक्रेन-रूस युद्ध में जान बचने पर भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के प्रति आभार जताया है जिन्होंने उनके लिए खाने-पीने और रहने की व्यवस्था की। स्टूडेंट ने कहा, 'जब कोई भारतीय यहां पहुंचता है तो उसे रहने के लिए जगह और खाना दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन होता है और डेट फाइनल की जाती है कि उन्हें कब स्वदेश ले जाया जाएगा।'

यूरोपीय संघ, जापान से मेलामाइन के आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय की शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने लैमिनेट्स में इस्तेमाल होने वाले मेलामाइन के यूरोपीय संघ, जापान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से होने वाले आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की है। डीजीटीआर ने सस्ती दरों पर आयात होने वाली खेप से घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए यह कदम उठाया है।

महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सस्ती दरों पर मेलामाइन के आयात किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद की गई पड़ताल के बाद डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया था कि इन देशों से मेलामाइन के आयात की मात्रा वास्तविक एवं सापेक्षिक दोनों संदर्भों में बढ़ गयी है। डंपिंग आयात की वजह से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की स्थिति बनती देखी गई। महानिदेशालय ने इन देशों से मेलामाइन के आयात पर 119 डॉलर प्रति टन और 428 डॉलर प्रति टन के दायरे में डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की है। इस सिफारिश के आधार पर वित्त मंत्रालय तीन महीने के भीतर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने के बारे में अंतिम निर्णय करता है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने डीजीटीआर को सौंपे अपने आवेदन में कहा था कि यूरोपीय संघ, जापान, कतर और यूएई से आयात किए जाने वाले मेलामाइन पर डंपिंग संबंधी आरोपों की पड़ताल की जाए।

मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल की नई डील 30 साल पुरानी कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुआई वाले रिलायंस समूह की रिटेल इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने एक नई डील की है। दरअसल, रिलायंस रिटेल ने लग्जरी फैशन हाउस अब्राहम एंड ठाकोर में बहुलांश हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है। हालांकि कंपनी ने निवेश के जरिये हासिल हिस्सेदारी के बारे में जानकारी नहीं दी है।

30 साल पुरानी कंपनी

अब्राहम एंड ठाकोर की स्थापना 30 साल पहले हुई थी। साल 1992 में डेविड अब्राहम और राकेश ठाकोर ने इसका गठन किया था। बाद में इस कंपनी से केविन निगली भी जुड़े जिसके बाद इसे

संक्षिप्त रूप में 'ए एंड टी' के नाम से जाना गया। रिलायंस रिटेल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, "अब्राहम एंड ठाकोर हाउस में सामग्री के दिलचस्प उपयोग और पारंपरिक कपड़ा तकनीकों पर नई सोच ने ब्रांड के प्रति आकर्षण पैदा किया है।" उन्होंने कहा, "हम वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के लिये भारतीय शिल्प कौशल की अनूठी अभिव्यक्ति लाने को लेकर ब्रांड के साथ साझेदारी के लिये उत्साहित हैं।"

वहीं, डेविड अब्राहम ने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से ए एंड टी ब्रांड की उपस्थिति का विस्तार होगा और 'फैशन' और 'लाइफस्टाइल' कलेक्शन दोनों एक साथ लाएंगे जिसमें घरेलू सामान भी शामिल होंगे। इस अधिग्रहण के बाद भी डेविड अब्राहम, राकेश ठाकोर और केविन निगली इस ब्रांड से जुड़े रहेंगे।

हर उम्र के मरीजों के लिए कारगर
अरोमा स्पाईन थेरेपी

अरोमा वर्ल्ड प्रा.लि. जो कि भारतीय कम्पनी है जिसे अरोमा क्योर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अरोमा वर्ल्ड की थेरेपी प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्राकृतिक थेरेपी के १०० से भी ज्यादा सिद्धांतों को माना है। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज अपने शरीर को स्वस्थ और जीवन को खुशलहाल तरीके से जिया करते थे। अरोमा वर्ल्ड आप सभी को आमंत्रित करता है अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं और इलाज करवा कर थक चुके हैं, तो एक बार अरोमा वर्ल्ड में जरूर आयें और २१वीं सदी के इस अद्भुत अविष्कार से अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म करें।

डायनामिक अगीरा स्टोन

अगीरा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सूर्य की कोमल किरणे यह एक प्राकृतिक स्टोन है यह साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड की पहाड़ों की चट्टानों से निकाला जाता है, जो आपको सेहत और ऊर्जा देता है। डायनामिक अगीरा स्टोन की दो खासियत हैं - **1. छह तरह के मिनिरल्स और 2. एफएआर इंफ्रा रेड रायस**

जिसकी वजह से खून का साफ होना, नसों का खुलना, शरीर की गंदगी का बाहर आना, कोशिकाओं को चार्ज करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हड्डियों को मजबूत कर मांसपेशियों को लचीला बनाना, खून के संचार को सही करना, एनर्जी लेवल को बढ़ाना आदि प्रमुख काम हैं।

शुगर, बी.पी., जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, स्लीप डिक्स, घुटनों का दर्द, मायग्रेन, नींद नहीं आना, कान की बीमारी, मोतियाबिंद, चश्मा लगा होना, साईनस की समस्या, हार्ट में ब्लोकेज होना, सांस की बीमारी, सर्वायकल का दर्द, थायराईड, मोटापा, कमर में गेप, हिप्स ज्वाईंट की समस्या, पोस्टेज, प्रेगनेन्सी की समस्या, पीरियड की समस्या, बच्चेदानी ब्लॉक होना, बच्चेदानी में सुजन होना, किडनी की बीमारी, लिवर में सुजन होना, गैस, एसिडिटी होना, पथरी की समस्या, बाल झड़ना, पिम्पल्स होना, डार्क सर्कल, खून की कमी होना, नसों की बीमारी, नसों में ब्लॉक होना, साईटिका की समस्या, याददाश्त में कमजोरी, चर्म रोग, स्कीन की बीमारी, सोराईसेस की समस्या, लकवा, कन्धों में दर्द, बच्चों में हाईट की समस्या, बच्चों में कमजोरी होना, ब्रेन ट्यूमर, शरीर में गिठान होना, शरीर में खून की कमी, खून की गठान बनना, वेरीकोसवेन, पाईल्स की समस्या, महिलाओं को सफेद पानी की समस्या, पेशाब बार-बार आना आदि बीमारियों का ईलाज बिना दवाई गोली, ऑपरेशन, इंजेक्शन के बिना इलाज किया जाता है। एक बार आकर थेरेपी का अनुभव जरूर लीजिए।

पता -161/ 12 नंदा नगर गुरुद्वारे के पास पाटनीपुरा इंदौर। मोबाइल नंबर- 98932 70995

उमंग-उल्लास के इस माह में जरूर करें यह काम

उमंग-उल्लास और रंगों का महीना कहे जाना वाला फाल्गुन माह वर्ष का अंतिम माह है। होली, महाशिवरात्रि जैसे व्रत-त्योहार आने के साथ इस माह का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि फाल्गुन माह में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था। इस कारण इस माह चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस माह कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। इस मास को आनंद और उल्लास का माह कहा जाता है। फाल्गुन माह में सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इस माह सफेद फूल, दही, सफेद शंख, चीनी, चावल, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। फाल्गुन माह में हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखें। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के दर्शन करें और उनकी रोशनी में बैठकर चंद्रदेव का स्मरण करें। फाल्गुन माह में शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें। शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। इस माह फलों का सेवन करना चाहिए। जीवन में उल्लास और उमंग लाने के लिए इस माह रंगीन और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस माह भगवान श्रीकृष्ण की नियमित उपासना करें। पूजा में फूलों का खूब इस्तेमाल करें। भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें। मां लक्ष्मी को इस माह गुलाब या इत्र अर्पित करें। फाल्गुन मास में दान का विशेष महत्व है। इस माह जरूरतमंदों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। मान्यता है कि इस माह लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस माह गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस माह भूलकर भी अपने से बड़ों का अपमान न करें और किसी से भी विवाद न करें। फाल्गुन माह में घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी में नियमित जल प्रदान करें। रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन माह उत्तम माना जाता है। इस माह भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। मां लक्ष्मी की पूजा से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है।

रोगों से मुक्ति पाने की शक्ति प्रदान करता है गंगाजल

मां गंगा सभी का उद्धार करने वाली हैं। उनकी कृपा से दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। संकट से मुक्ति के लिए मां गंगा की उपासना बहुत मायने रखती है। मान्यता है कि गंगाजल का स्पर्श करने मात्र से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गंगाजल से स्नान या इस पवित्र जल का सेवन करने से कई रोगों का खतरा कम हो जाता है। गंगाजल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। वास्तु शास्त्र में गंगाजल के प्रयोग से कई दोषों को दूर करने के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। हर सोमवार भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। गंगाजल के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य और वस्तु शुद्ध हो जाते हैं। कोई भी पूजा बिना गंगाजल अधूरी मानी गई है। घर में साफ-सफाई के बाद स्नान कर पूजा करें और गंगाजल का छिडक़ाव करें। गंगाजल प्रत्येक कमरे में छिडक़ें। इससे मन शांत रहता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। गंगाजल के सेवन से निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। मान्यता है कि गंगाजल के प्रयोग से आठ से भी ज्यादा बीमारियों का उपचार संभव है। मान्यता है कि गंगाजल को घर में रखने से हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है। कभी भी दूषित हाथों से गंगाजल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पवित्र गंगाजल को हमेशा तांबे या चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। घर में जहां गंगाजल रखा जाता है, वहां साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि हर दिन गंगा जल पीने से मनुष्य निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है।

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

विभिन्न शिवलिंगों पर अभिषेक करने के मिलते है कई फल

वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक का हर रोज करना चाहिए लेकिन महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार का दिन कुछ खास है यह दिन भगवान शिव जी का विशेष रूप से प्रिय माना जाता है कई ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव का अभिषेक करने पर उसकी कृपा हमेशा बनी रहती है मनोकामना पूरी होती है धर्म सिंधु के दूसरे परिच्छेद के अनुसार अगर किसी खास फल की इच्छा हो तो भगवान शिव के विशेष शिवलिंग की पूजा करना चाहिए यहां जानिए किस धातु से बने शिवलिंग की पूजा करदे से कौन सा फल प्राप्त होता है

1 सोने के शिवलिंग पर अभिषेक करने से सत्यलोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है

2 मोती के शिवलिंग पर अभिषेक करने से रोगों का नाश होता है

3 हीरे से निर्मित शिवलिंग पर अभिषेक करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है

4 पुखराज के शिवलिंग पर अभिषेक करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है

5 स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है

6 नीलम के शिवलिंग पर अभिषेक आदि से सम्मान की प्राप्ति होती है

7 चांदी से बने शिवलिंग पर अभिषेक करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है

8 ताबे के शिवलिंग पर अभिषेक करने से पितरों की मुक्ति होती है

9 लोहे के शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है

10 आटे से बने शिवलिंग पर अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति होती है

मार्च में बुध, सूर्य और शुक्र की बदलेगी चाल

ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का मानवीय जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मार्च के महीन में सूर्य, शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करेंगे। आइए जानते हैं मार्च माह में सूर्य, शुक्र और बुध के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों को होगा फायदा...

मेष राशि- इस दौरान पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ परिणाम मिल सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

मिथुन राशि- धन से जुड़े मामलों में सफलता हासिल होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। लेन- देन के लिए समय शुभ है।

वृश्चिक राशि- इस दौरान आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। गोचर काल में आपको सफलता हासिल होगी। धन आगमन के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है।

मकर राशि- इस दौरान आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

फरवरी में भी वाहनों की घरेलू बिक्री पर पड़ा असर पर टाटा मोटर्स और महिंद्रा का प्रदर्शन बेहतर

नयी दिल्ली। एजेंसी

अग्रणी वाहन निर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंदै, टोयोटा और होंडा की थोक बिक्री में फरवरी में गिरावट दर्ज की गई। सेमीकंडक्टर की किल्लत बनी रहने से वाहनों की बिक्री पर असर देखा गया है। हालांकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा और एमजी मोटर ने एक साल पहले की तुलना में फरवरी 2022 में वाहनों की थोक बिक्री में वृद्धि दर्ज की।

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने फरवरी के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि उसकी घरेलू बिक्री 8.46 प्रतिशत गिरकर 1,40,035 इकाई रही जबकि फरवरी 2021 में यह 1,52,983 इकाई रही थी। एमएसआई ने एक बयान में कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की किल्लत ने मुख्य तौर पर घरेलू बाजार में बिकने वाले वाहनों के उत्पादन पर हल्का असर डाला। हालांकि कंपनी ने इस असर को कम करने के लिए हरसंभ कदम उठाए हैं।'

इसी तरह देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी हुंदै मोटर इंडिया ने फरवरी में 44,050 इकाइयों की थोक बिक्री के साथ 14.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। कंपनी ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत से निपटने के लिए वह सभी वैकल्पिक तरीके अपना रही है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कहा कि उसकी घरेलू बिक्री फरवरी में 38 प्रतिशत गिरकर 8,745 इकाई पर आ गई। इसी तरह होंडा कार्स की घरेलू बिक्री फरवरी 2022 में 23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,187 इकाई रह गई। होंडा कार्स इंडिया के निदेशक (विपणन एवं बिक्री) युइची मुराता ने कहा, 'हमें भविष्य में हालात सुधरने की उम्मीद है ताकि हम बाजार की मांग को अधिक असरदार ढंग से पूरा कर सकें।' इसके उलट, टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री में 47 प्रतिशत की जोरदार उछाल दर्ज करते हुए 39,981 वाहनों की बिक्री की। एक साल पहले इसी महीने में कंपनी ने 27,225 इकाई बेचे थे। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घरेलू बाजार में पिछले महीने 80 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के साथ 27,663 इकाइयों की बिक्री की। कंपनी ने फरवरी 2021 में 15,391 इकाइयों की बिक्री की थी।

स्कोडा ऑटो इंडिया के लिए भी फरवरी का महीना थोक बिक्री के लिहाज से अच्छा साबित हुआ। मझोले आकार की एसयूवी कुशाक की सफलता के दम पर कंपनी ने पिछले महीने 4,503 वाहनों की बिक्री के साथ पांच गुना वृद्धि दर्ज की। इसी तरह एमजी मोटर इंडिया ने कहा कि फरवरी में उसकी खुदरा बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 4,528 इकाई हो गई। निसान इंडिया ने भी घरेलू बाजार में पिछले महीने 2,456 वाहनों की बिक्री की।

अटलांटिक में डूबा पोर्श कारें ले जा रहा जहाज

कुछ दिन पहले इंजन में लग गई थी आग

सिंगापुर। एजेंसी।

जर्मनी से पोर्श कारें लेकर अमेरिका जा रहा एक मालवाहक जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। जहाज प्रबंधक और पुर्तगाल की नौसेना ने बताया कि इससे 13 दिन पूर्व जहाज के इंजन में आग लग गई थी। इसके बाद इसे खींचकर ले जाया जा रहा था। एमओएल शिप मैनेजमेंट कंपनी ने सिंगापुर में बताया कि यह हादसा पुर्तगाल के एजोरेस टापू से करीब 400 किलोमीटर दूर हुआ। बचाव दल आग बुझा चुका था। 200 मीटर (650 फुट लंबा) जहाज स्टारबोर्ड पर लिस्टेड था।

पुर्तगाल की नौसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि उसकी वायुसेना जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों को पहले ही बचा चुकी थी। जहाज के आकार के मुताबिक, इस पर 4000 वाहनों को ले जाया जा सकता था। पोर्श कंपनी ने यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि इस पर लदी कारें किस मॉडल की थीं। आग के कारण इंजन नहीं कर रहा था काम, खींचकर ले जाया जा रहा था।

लिथियम बैटरी हो सकती है आग का कारण

पुर्तगाली अधिकारियों ने बताया कि इस जहाज पर इलेक्ट्रिक और तेल से चलने वाली दोनों तरह की कारें लदी हुई थीं। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि 16 फरवरी को आग लगने का कारण लिथियम बैटरी से हुआ कोई स्पार्क हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

समुद्र में प्रदूषण का भी था खतरा

अधिकारियों को डर था कि जहाज डूबने के कारण समुद्र में प्रदूषण फैल सकता है। जहाज में 2200 टन ईंधन था और 18,700 टन लदान करने की क्षमता थी। हालांकि पुर्तगाली नौसेना ने वक्तव्य जारी कर बताया है कि जिस स्थान पर जहाज डूबा है, वहां महासागर की सतह पर काफी कम तेल दिखाई दिया है। हालांकि पुर्तगाली वायुसेना के प्लेन और नौसेना के जहाज प्रदूषण पर नजर बनाए हुए हैं।

लाइफस्टाइल ने मौसम के लिए आकर्षक कलर्स, बेहतरीन कीमत में नई रेंज

एजेंसी।

भारत का अग्रणी फैशन डेस्टिनेशन लाइफस्टाइल ने अपना नया स्प्रिंग/समर कलेक्शइन पेश किया है। फैशन के मामले में श्रेष्ठा सौंदर्य और गर्मियों के अनुकूल दोनों खूबियों से भरपूर यह कलेक्शइन देखकर आप अपने आपको रोक नहीं पाएंगे और इसकी कीमत बहुत ही वाजिब रखी गई है। नए कलेक्शन के साथ लाइफस्टारइल का फोकस वर्सटाइल क्रीएशन को प्रस्तुरत करने पर है और ये कंफर्ट और स्टालइल के मामले में बेहतरीन हैं जो आज के दौर के फैशन शॉपर्स को लुभाते हैं। चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हों या फिर दोस्तों के साथ बाहर मौजमस्ती। करनी हो, लाइफस्टाऔइल का नया कलेक्शोन आपकी सभी जरूरतों पर खरा उतरता है। अपैरल, फुटवीयर, हैंडबैग आदि बहुत ही ट्रेंडी स्टा,इल्सट में पेश किए गए हैं जो वाइब्रेंट फीलगुड कराने वाले हैं। इनकी आकर्षक कीमतें कलेक्श न को और भी ज्यादा डिजायरेबल बना देती हैं। लाइफस्टाटइल की नई स्प्रिंग/समर रेंज बेहतरीन है और कलर्स, प्रिंट्स और सिलआउट्स की उचित सजावट इसको इस मौसम के लिए बेहद अनुकूल बनाती है। महिलाओं को यह कलेक्शैन बेशक आकर्षित करेगा। इस रेंज में फ्लोरल मैक्सी-लेंथ गाउन और टियर्ड ड्रेसेज के समर शेड्स में लाइलेक, बटर येलो, फ्यूशिया पिंक और अन्या शेड्स किसी भी केजुअल दिन के लिए आकर्षक हैं। इसके अलावा खूबसूरत ऑफ-शॉल्डमर्स, स्लिट और बस्टियर ड्रेसेज और गर्मियों में बेहद पसंद किए जाने वाली क्रोशेट ड्रेसेज-साटिन में फेमाइन शिलआउट्स और टाइ-डाई प्रिंट पार्टी लुक के लिए परफेक्ट हैं। इन ड्रेसेज की कीमत मात्र 699 रुपये से शुरू होती है। पुरुष अपने लिए ऑल डे कंफर्ट कॉटन और लिनेन्सवर निटेड शर्ट्स और ट्राउजर्स देख सकते हैं। ऑल न्यू 'मॉमेंटम सीरीज' में फ्लेक्सीकबल गारमेंट्स की पूरी रेंज प्रस्तुत की गई है जो हर अवसर के लिए अनुकूल है और इसमें कंफर्ट और स्टापइल का बेहतरीन तालमेल है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए सुपीरियर टेक्नो लॉजी '24/7 हाई-पर' डेनिम पेश की गई हैं जो वीकेंड आउटिंग के लिए परफेक्टौ हैं।

कॉरपोरेट मंत्रालय का कंपनियों के खिलाफ सभी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में दर्ज करने का निर्देश

नयी दिल्ली। एजेंसी

हितधारकों को निशाना बनाकर होने वाले अनधिकृत संवाद की संभावित घटनाओं को रोकने के प्रयासों के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी पंजीयक और क्षेत्रीय निदेशकों को कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतें मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में दर्ज करने का निर्देश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री 'एमसीए21' में सारी जानकारियां डालने के बाद हर शिकायत की एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) तैयार होती है और फिर आगे जाकर उस मामले से संबंधित हर संवाद के लिए इसी संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों को सूचित किया है कि कंपनी पंजीयक (आरओसी) और सभी स्थानों के क्षेत्रीय निदेशकों (आरडी) को निर्देश दिया गया है कि कंपनियों और एलएलपी के खिलाफ शिकायतों से जुड़े सभी मामलों, निरीक्षण, पूछताछ, जांच और अभियोग की जानकारी एमसीए21 में डाली जाए और उसके बाद ही कोई पत्र, नोटिस या आदेश जारी किया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि धोखेबाज तत्वों द्वारा हितधारकों का शोषण रोका जा सका। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के संवाद में एसआरएन रहने से हितधारकों को भी यह पता रहेगा कि जो संवाद उन्हें प्राप्त हुआ है वह अधिकृत है। एमसीए21 मंत्रालय में सांविधिक फाइलिंग जमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्टल है।

हायर ने 'मेक इन इंडिया' पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

पुणे इंडस्ट्रियल पार्क में डीप फ्रीजर फैक्ट्री का शुभारंभ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी और लगातार 13 वर्षों तक प्रमुख उपकरणों के क्षेत्र में दुनिया के नंबर 1 ब्रांड, हायर ने रंजनगांव, पुणे में अपने पहले इंडस्ट्रियल पार्क में डीप फ्रीजर बनाने के लिए अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस नई फैक्ट्री के साथ, हायर ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करते हुए, स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गईकेंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।

इसके अलावा, यह निवेश भारत में हायर की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और बेहतर गुणवत्ता वाले डीप फ्रीजर उत्पादों की वार्षिक उत्पादन क्षमता को 5 लाख यूनिट तक बढ़ाएगा। हायर भारत में स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग के जरिये प्रीमियम प्रोडक्ट्स के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई डीप फ्रीजर फैक्ट्री की स्थापना के साथ कंपनीस्थानीय बाजार की उभरती जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम बनेगी। इसी तरह, यह विस्तार बेहतर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए एक खुले मंच के रूप में काम करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादों के कम आयात के साथ व्यापक विकास संभव हो सकेगा।

उद्घाटन समारोह में, हायर ने कॉमर्शियल फ्रीजर सेगमेंट में 4 नए एसकेयू लॉन्च करने की भी घोषणा की, जो एचएफसी-350डीएम5, एचएफसी-588डीएम5-हार्ड टॉप मॉडल और एचएफसी-300जीएम5, एचएफसी-400जीएम5-फ्लैट ग्लास टॉप मॉडलहैं। इन नए एसकेयू में 50% तक ऊर्जा बचत के लिए 5-स्टार रेटिंग और बेहतर कूलिंग दक्षता के लिए 5 साइड फ्रीजिंग मौजूद है। हायर ग्रुप ने भारत में अपना पहला इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वर्ष 2015 में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, हायर

ने पुणे इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह इंडस्ट्रियल पार्क सभी प्रमुख श्रेणियों में विश्व स्तरीय, उच्च गुणवत्ता वाले होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन का केंद्र है। इसके अलावा, 'इंस्पायर्ड लिविंग' के ब्रांड दर्शन को साकार करते हुए, कंपनी लगातार देश में नए बदलावों और उत्पादन में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अपना ध्यान दे रही है।

इस अवसर पर, हायर अप्लायंसेज इंडिया के प्रेसिडेंट श्री सतीश एनएस ने कहाकि 'पुणे स्थित अपने इंडस्ट्रियल पार्क में नई डीप फ्रीजर फैसिलिटी की स्थापना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो हमें अपने कॉमर्शियल और घरेलू फ्रीजर दोनों सेगमेंट्स की मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। यह फैक्ट्री न केवल हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए अधिक टाइम-एफिशिएंट तरीके से ग्राहकों के अनुकूल समाधान प्रदान करने में भी हमारी मदद करेगी। इससे आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होगी और साथ ही निकट भविष्य में भारत से निर्यात भी बढ़ेगा।'

कुष्ठ रोग की पृष्ठभूमि से जुड़े युवाओं का यूथ समागम

पूर्व छात्र नेटवर्क बनाने के लिए सासाकावा-इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन की पहल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कुष्ठ रोगियों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित संगठन, सासाकावा-इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन (एस-आईएलएफ) ने कुष्ठ रोग की पृष्ठभूमि वाले युवाओं का पूर्व छात्र नेटवर्क बनाने की पहल की। यह मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला नेटवर्क है। 2012 से, एस-आईएलएफ ने राज्य में कुष्ठ कॉलोनियों के 130 से अधिक युवाओं को उच्च व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने में सहयोग दिया है। इनमें से कई एस-आईएलएफ स्कॉलर्स अब प्रतिष्ठित संगठनों में काम कर रहे हैं और उनका जीवन अब सुव्यवस्थित है। इन युवाओं में मुख्यधारा के लोगों और कुष्ठ पृष्ठभूमि से अन्य युवाओं को प्रभावित करने की क्षमता है, जिसे देखते हुए, एस-आईएलएफ ने स्कॉलर्स यूथ लीडरशिप काउंसिल बनाने के उद्देश्य से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। 70 से अधिक स्कॉलर्स अपने नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाने के लिए दिन भर चलने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए, जिसका समापन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्कॉलर्स ने तैयार किया था। कार्यक्रम के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सहयोग दिया था, जिसमें स्कॉलर्स को उद्योग के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। इंदौर के होटल अमर विलास में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों में श्री तरुण दास, चेयरमैन, एस-आईएलएफ; कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सौरभ सिंगला, चेयरमैन-सीआईआई-मध्य प्रदेश और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डेरेक पैट्सी लोबो, ट्रस्टी एस-आईएलएफ शामिल रहे। यूथ लीडरशिप काउंसिल एक विविधापूर्ण, युवाओं द्वारा संचालित समूह है जो नेतृत्व को बनाए रखने, परिवर्तन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय है। इसका उद्देश्य समाज में कुष्ठ रोग को एक कलंक की तरह देखने की जो मानसिकता बनी हुई है, उसे समाप्त करना है तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के बीच अपनी नेटवर्किंग के जरिये समान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना है। एस-आईएलएफ अन्य राज्यों में पूर्व छात्रों के नेटवर्क की स्थापना करने के लिए अपना समर्थन देना जारी रखेगा।

रिजर्व बैंक ने अपने वित्तीय साक्षरता अभियानों के असर का पता लगाने की कवायद शुरू की

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उसके द्वारा शुरू किए गए मल्टीमीडिया जागरूकता अभियानों के असर का पता लगाने की कवायद शुरू की है। आरबीआई आम लोगों को बैंकिंग नियमों के बारे में शिक्षित करने के लिए 'आरबीआई कहता है' नाम से एक अभियान चलाता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक जनता को अच्छी और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में भी जागरूक करता है। यह एक बहुमीडिया बहुभाषी अभियान है, जिसमें एसएमएस, प्रिंट, टेलीविजन चैनल, रेडियो, होर्डिंग, वेबसाइट और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। इस अभियान के असर का पता लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने कुछ चुनिंदा संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं।

यूक्रेन युद्ध से चालू वित्त वर्ष में आयात बिल बढ़कर 600 अरब डॉलर होने की आशंका: रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

यूक्रेन में जारी संकट के चलते चालू वित्त वर्ष में देश का आयात बिल बढ़कर 600 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। इसका कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रत्न और आभूषण, खाद्य तेल और उर्वरक के आयात पर भारत की निर्भरता और रुपये के मूल्य में गिरावट है। इससे महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह कहा।

रिपोर्ट के मुताबिक रूस-यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए भू-राजनीतिक जोखिम से खनिज तेल और गैस, रत्न और आभूषण, खाद्य तेल और उर्वरक जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। इसके चलते वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तुओं का आयात 600 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है, जो चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में 492.9 अरब अमेरिकी डॉलर था। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने रिपोर्ट में कहा कि इसके चलते मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होगी, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपये के मूल्य में गिरावट हो सकती है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत में 5 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी होने पर व्यापार या चालू खाता घाटा 6.6 अरब डॉलर बढ़ता है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।